भारतीय जंगलों को खतरा एवं उनका प्रमाणीकरण

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-III
(पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हमेशा से पर्यावरण के लिए चिंता का विषय रहा है लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ, वनों की कटाई हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर एक गंभीर रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखते हुए, वन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्सर्जित होता है। 2021 में ग्लासगो जलवायु बैठक में, 100 से अधिक देशों ने 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और उलटना शुरू करने का संकल्प लिया।

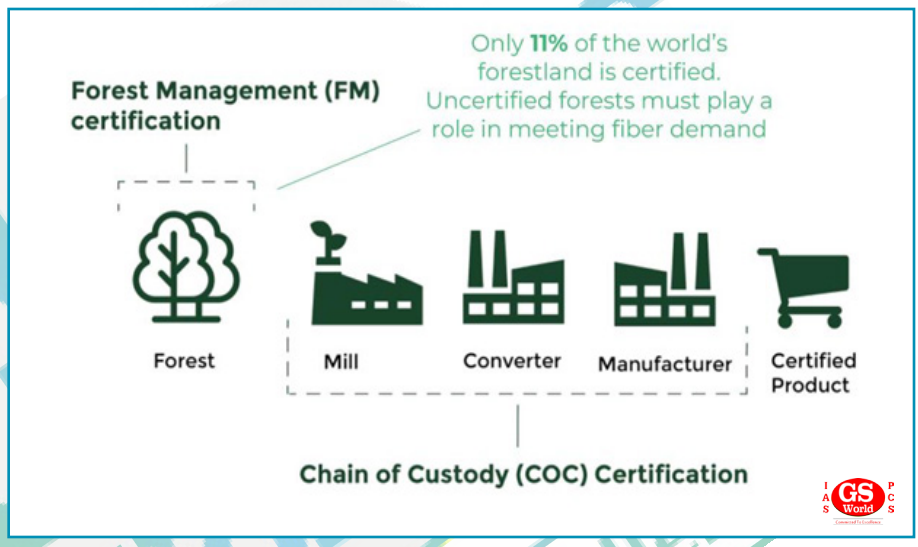

विश्व एवं वन उत्पादों का विनियमन

पर्यावरण के अनुकूल छवि पेश करने के इच्छुक कई देश और कॉरपोरेट अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि वे किसी भी उत्पाद की खपत से बचें जो कि वनों की कटाई या अवैध कटाई का परिणाम हो सकता है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने बाजारों में वन-आधारित उत्पादों के प्रवेश और बिक्री को विनियमित करने वाले कानून पारित किए हैं। यह वह जगह है जहाँ प्रमाणीकरण उद्योग एक बहु-परत लेखापरीक्षा प्रणाली की पेशकश करता है, जो लकड़ी, फर्नीचर, हस्तकला, कागज और लुगदी, रबर, और कई अन्य जैसे वन-आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधता और सतता को प्रमाणित करना चाहता है।

सतता और प्रमाणपत्र

वनों की कटाई को रोकने का मतलब यह नहीं है कि उत्पादों के लिए वनों को स्थायी तरीके से काटा नहीं जा सकता है। वास्तव में वनों के लिए पेड़ों की समय-समय पर कटाई आवश्यक और स्वस्थ है। पेड़ों का एक जीवनकाल होता है, जिसके आगे वे मर जाते हैं और सड़ जाते हैं। साथ ही एक निश्चित आयु के बाद पेड़ों की कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता संतृप्त हो जाती है। नए और नए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में अधिक कुशल होते हैं। समस्या तभी पैदा होती है जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है और जंगलों की कटाई उनके प्राकृतिक पुनर्जनन को पीछे छोड़ देती है।

लगभग तीन दशक पुराना वैश्विक प्रमाणन उद्योग स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के माध्यम से यह स्थापित करने के एक तरीके के रूप में शुरू हुआ कि क्या वनों को एक स्थायी तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था। वर्षों से, वानिकी क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रमाणपत्रों की एक श्रृंखला की पेशकश की गई है। वनों और वन-आधारित उत्पादों के सतत प्रबंधन के लिए दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं (कुछ अन्य कम व्यापक रूप से स्वीकृत भी हैं)। एक फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल या एफएससी द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन या पीईएफसी द्वारा। एफएससी प्रमाणीकरण अधिक लोकप्रिय और मांग में है, और अधिक महंगा भी है।

एफएससी या पीईएफसी जैसे संगठन केवल मानकों के विकासकर्ता और मालिक हैं, उदाहरण के लिए, मानकीकरण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (ISO) या अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (BIS)। वे वन प्रबंधकों या वन-आधारित उत्पादों के निर्माताओं या व्यापारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के मूल्यांकन और ऑडिटिंग में शामिल नहीं हैं। यह एफएससी या पीईएफसी द्वारा अधिकृत प्रमाणन निकायों का काम है।

प्रमाणन निकाय अक्सर अपने काम को छोटे संगठनों को उपठेके पर देते हैं। PEFC अपने स्वयं के मानकों के उपयोग पर जोर नहीं देता। इसके बजाय, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह किसी भी देश के 'राष्ट्रीय' मानकों का समर्थन करता है यदि वे उसके साथ संरेखित हों। प्रस्ताव वन प्रबंधन (एफएम) और चेन ऑफ कस्टडी (सीओसी) पर प्रमाणीकरण के दो मुख्य प्रकार हैं। सीओसी प्रमाणन का मतलब मूल से लेकर बाज़ार तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लकड़ी जैसे वन उत्पाद की ट्रेसबिलिटी की गारंटी देना है।

भारत में वन प्रमाणीकरण

वन प्रमाणन उद्योग भारत में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा है। वर्तमान में केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणित हैं। यूपी वन निगम (यूपीएफसी) के इकतालीस डिवीजन पीईएफसी-प्रमाणित हैं, जिसका अर्थ है कि पीईएफसी द्वारा समर्थित मानकों के अनुसार उनका प्रबंधन किया जा रहा है। इन मानकों को नई दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट (एनसीसीएफ) द्वारा विकसित किया गया है।

वन प्रमाणन क्या है?

- वन प्रमाणन, रियो अर्थ समिट के बाद 1990 के दशक में शुरू किया गया एक वैश्विक आंदोलन है। प्रमाणन एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा जंगलों के बाहर जंगलों और पेड़ों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक बाजार-आधारित गैर-नियामक संरक्षण उपकरण है। जैसा कि कई विकसित देशों ने अपने देशों में गैर-प्रमाणित लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उत्पादों और लकड़ी-आधारित सामानों के आयात पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात के लिए स्थायी वन प्रबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।
- वन प्रमाणन वन निगरानी, लकड़ी और लुगदी उत्पादों और गैर-लकड़ी वन उत्पादों का पता लगाने और लेबल लगाने के लिए एक तंत्र है जहां पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबंधन की गुणवत्ता को सहमत मानकों की एक श्रृंखला के खिलाफ आंका जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो एक स्वतंत्र पार्टी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी करने की ओर ले जाती है, जो यह सत्यापित करती है कि जंगल का एक क्षेत्र एक परिभाषित मानक के अनुसार प्रबंधित है।

वनों और वन आधारित उत्पादों के सतत प्रबंधन के लिए दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक

1. फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल (FSC) द्वारा विकसित- अधिक लोकप्रिय और महंगा।
2. प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन (PEFC) द्वारा विकसित-किसी भी देश के 'राष्ट्रीय' मानकों का समर्थन करता है।

प्रमाणीकरण के दो मुख्य प्रकार -

1. **वन प्रबंधन इकाई प्रमाणन (एफएमयू):** वन प्रबंधन प्रमाणन, एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सत्यापित करती है कि वन/वृक्षारोपण का एक क्षेत्र जहाँ से लकड़ी, फाइबर और अन्य गैर-इमारती वन उत्पादों को निकाला जाता है, एक परिभाषित मानक के अनुसार प्रबंधित किया जाता है।
2. **चेन ऑफ कस्टडी (सीओसी):** सीओसी प्रमाणीकरण प्रमाणित वन से बिक्री के बिंदु तक वन उत्पादों को ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद प्रमाणित वन से उत्पन्न हुआ है।

कुछ अन्य राज्यों ने भी प्रमाणन प्राप्त किया, लेकिन बाद में बाहर हो गए। महाराष्ट्र में भामरागढ़ वन प्रभाग, वन प्रबंधन के लिए एफएससी प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला था। बाद में, मध्य प्रदेश में दो डिवीजनों और त्रिपुरा में एक ने भी एफएससी प्रमाणन प्राप्त किया। UPFC के पास पहले भी FSC सर्टिफिकेशन था। हालांकि, ये सभी समय के साथ समाप्त हो गए। केवल यूपीएफसी ने अपना प्रमाणीकरण बढ़ाया लेकिन पीईएफसी के साथ।

कई कृषि वानिकी परियोजनाएं, जैसे कि ITC द्वारा संचालित और कई पेपर मिलों को भी वन प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त है। यहाँ के जंगल उद्योग के बंदी उपयोग के लिए हैं। बड़ी संख्या में सी. ओसी प्रमाणन हैं, लेकिन ड्रॉपआउट दर 40 प्रतिशत है। अब तक एफएससी द्वारा 1,527 वैध सीओसी प्रमाणन हैं और 1,010 निलंबित, समाप्त हो चुके हैं या समाप्त कर दिए गए हैं। भारत में अब तक कुल 105 संस्थाओं ने PEFC CoC प्रमाणन प्राप्त किया है, जिनमें से 40 की समय सीमा समाप्त हो गई है या उन्हें निलंबित या समाप्त कर दिया गया है।

भारत में वन प्रमाणीकरण

- सतत वन प्रबंधन के लिए प्रमाणन मानक (SFM) एक भारतीय गैर-लाभकारी संस्था, प्रमाणन और वन संरक्षण के लिए नेटवर्क (NCCF) द्वारा विकसित किया गया है। वहीं PEFC स्थायी वन प्रबंधन के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रदान करता है।
- एनसीसीएफ की स्थापना 2015 में वन-आधारित उद्योगों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, वन लेखा परीक्षकों और सरकारी वन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भारत के वनों, उनके उत्पादों और उनके टिकाऊ प्रबंधन को प्रमाणित करने के लिए मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- एनसीसीएफ की वन प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारत के वन प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करना है, जिसकी अक्सर वन अधिकार, वन क्षरण, जैव विविधता हानि, अतिक्रमण, जनशक्ति की कमी आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के लिए आलोचना की जाती है।

वन प्रमाणन का महत्त्व एवं आवश्यकता :-

- वन प्रमाणन को दुनिया भर में वन प्रबंधन के लिए एक कुशल उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। यह देखते हुए कि भारत के वन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक कार्य करते हैं, जो इस देश के 275 मिलियन से अधिक वन आश्रित लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। वनों की इन भूमिकाओं को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता है।

भारत-विशिष्ट मानक

भारत केवल प्रसंस्कृत लकड़ी के निर्यात की अनुमति देता है, लकड़ी की नहीं। वास्तव में, भारतीय जंगलों से काटी गई लकड़ी आवास, फर्नीचर और अन्य उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में लकड़ी की मांग सालाना 150-170 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 90-100 मिलियन क्यूबिक मीटर कच्ची लकड़ी भी शामिल है। बाकी मुख्य रूप से पेपर और पल्प की मांग को पूरा करने में जाता है।

भारत के वन हर साल लगभग 50 लाख क्यूबिक मीटर लकड़ी का योगदान करते हैं। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों की लगभग 85 प्रतिशत मांग जंगलों के बाहर के पेड़ों (टीओएफ) से पूरी होती है। करीब 10 फीसदी आयात किया जाता है। भारत का लकड़ी आयात बिल प्रति वर्ष 50,000-60,000 करोड़ रुपये है।

चूंकि टीओएफ इतना महत्वपूर्ण है, उनके स्थायी प्रबंधन के लिए नए प्रमाणन मानक विकसित किए जा रहे हैं। PEFC के पास पहले से ही TOF के लिए सर्टिफिकेशन है और पिछले साल FSC भारत-विशिष्ट मानकों के साथ आया था जिसमें TOF के लिए सर्टिफिकेशन शामिल था। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने जून 2022 में FSC के भारत मानकों का शुभारंभ किया।

सरकार के अपने मानक

भारत में निजी प्रमाणन निकायों के संचालन से बहुत पहले, सरकार वनों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मानकों को परिभाषित करने के लिए आगे बढ़ी थी। 2005 में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण मंत्रालय ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जैसे प्रासंगिक संस्थानों को राष्ट्रीय वन मानकों को तैयार करने के लिए कहा था। काफी काम किया गया था और ऐसे मानकों को स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया गया था। हालांकि प्रयास रंग नहीं लाया।

जब 2015 में एनसीसीएफ अस्तित्व में आया, भारत में पीईएफसी प्रमाणीकरण की पेशकश करते हुए, पर्यावरण मंत्रालय ने इसे आधिकारिक वैधता प्रदान करते हुए गवर्निंग बोर्ड में एक अधिकारी को नामित किया। लेकिन बाद में नामांकन वापस ले लिया गया। पिछले साल, मंत्रालय ने अपने नए भारत मानकों को लॉन्च करके एफएससी के साथ खुद को जोड़ा।

निजी प्रमाणन एजेंसियों की भूमिका, विशेष रूप से वन प्रबंधन प्रमाणन के संबंध में, प्रभावशाली सेवानिवृत्त वन अधिकारियों के एक समूह द्वारा निरंतर आलोचना की गई है। इस आलोचना और निजी प्रमाणन क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों के जवाब में, मंत्रालय ने आधिकारिक राष्ट्रीय वन मानकों को विकसित करने के प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया है।

सरकार का कहना है कि "प्रमाणन की स्वदेशी प्रणाली" सरल, पारदर्शी और छोटे किसानों और वृक्ष उत्पादकों द्वारा भी अपनाने में आसान होगी। बेंचमार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों का पालन करेंगे लेकिन भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य स्थायी रूप से विकसित और प्रबंधित वन उत्पादों को घरेलू बाजार में उपलब्ध कराना है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वन प्रबंधन इकाई प्रमाणन (एफएमयू), एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सत्यापित करती है कि वन/वृक्षारोपण का एक क्षेत्र जहाँ से लकड़ी, फाइबर और अन्य गैर-इमारती वन उत्पादों को निकाला जाता है, एक परिभाषित मानक के अनुसार प्रबंधित किया जाता है।
2. चेन ऑफ कस्टडी (सीओसी) प्रमाणीकरण, प्रमाणित वन से बिक्री के बिंदु तक वन उत्पादों को ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद प्रमाणित वन से उत्पन्न हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements-

1. Forest Management Unit Certification (FMU), is a process that verifies that an area of forest/ plantation from where timber, fiber and other non- timber forest products are extracted is managed according to a defined standard .
2. Chain of Custody (CoC) certification is a process of tracking forest products from a certified forest to the point of sale to ensure that the product originated from a certified forest.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : वन प्रमाणन क्या है? इसके महत्व एवं आवश्यकता को बताएं तथा भारत में वन के प्रमाणीकरण पर प्रकाश डालिए।

(250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ वन प्रमाणन क्या है बताएं।
- ❖ वन प्रमाणन के महत्व एवं आवश्यकता को बताएं।
- ❖ भारत में वन के प्रमाणीकरण के बारे में बताएं।
- ❖ संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।